इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1972)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 5 जनवरी, 1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 11 जनवरी, 1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया ।]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 29 जून, 1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 3 जुलाई, 1972 ई० को प्रकाशित हुआ ।]

इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2, 1921

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2, 1921 की धारा 16-घ का संशोधन

2—इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (जिसे एतद्पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 16-घ में —

(क) उपधारा (4) में, उसके प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड और उसके ठीक पूर्ववर्ती पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा तथा प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिये जायें, अर्थात्—

"ऐसा आदेश दिये जाने की अवधि प्रथमतः एक वर्ष से अधिक की न होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी संस्था के उचित प्रबन्ध को अनवरत रूप से सुनिश्चित करने के लिये ऐसा करना इष्टकर है, तो वह समय-समय पर आदेश का प्रवर्तन ऐसी अवधि के लिये, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक न हो, जिसे वह निर्दिष्ट करे, बढ़ा सकती है, किन्तु इस प्रकार कि उक्त आदेश के प्रवर्तन की कुल अवधि, जिसके अन्तर्गत इस उपधारा के अधीन प्रारम्भिक आदेश में निर्दिष्ट अवधि भी है, पांच वर्ष से अधिक न हो :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार ऐसे आदेश को किसी भी समय विखण्डित कर सकती है ;";

[उद्देश्य और कारणों के विवरत के लिये कृपया दिनांक 30 अगस्त, 1971 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।]

(ख) उपधारा (5) में शब्द, "उक्त संस्था के ले न लिये जाने" के स्थान पर शब्द "आदेश न दिये जाने" रख दिये जायं, तथा निम्नलिखित को उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड के रूप में बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि इससे प्राधिकृत नियंत्रक को किसी ऐसी सम्पत्ति का (प्रबन्ध के सामान्य क्रम में माह प्रति माह किराये पर देने के सिवाय) अन्तरण करने या उसे भारित करने (सिवाय राज्य सरकार से संस्था के लिये कोई सहायता अनुदान प्राप्त करने की शर्त के रूप में) का अधिकार प्राप्त होता है।";

(ग) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात् :—

"(5-क) यदि उपधारा (4) में अभिदिष्ट सिफारिश प्राप्त होने पर राज्य सरकार का उस उपधारा के पैरा (क) अथवा पैरा (ख) में उल्लिखित परिस्थितियों के विद्यमान होने का समाधान हो जाय और यह भी समाधान हो जाय कि विशेष और अपवादिक कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, उस उपधारा के अधीन कार्यवाही करना पर्याप्त रूप से प्रभावकारी नहीं होगा और संस्था के हित में यह आवश्यक है कि उसका प्रबन्ध तुरन्त एक प्राधिकृत नियन्त्रक को सौंपा जाय, तो राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसी अवधि के लिये जो आदेश में निर्दिष्ट की जायं प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति कर सकती है और वह प्राधिकृत नियन्त्रक प्रबन्धाधिकरण या ऐसे किसी व्यक्ति का अपवजन करते हुये संस्था का प्रबन्ध, जिसमें संस्था की भूमि, भवनों, निधियों तथा संस्था के या उसमें निहित अन्य परिसम्पत्ति का प्रबन्ध सम्मिलित है, अपने हाथ में ले सकता है और जब भी कभी प्राधिकृत नियन्त्रक द्वारा इस प्रकार प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया जाय, उसे, केवल ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुये जो राज्य सरकार आरोपित करे, संस्था के प्रबन्ध में वे सब अधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो इस उपधारा के या उपधारा (4) के अधीन आदेश न दिये जाने की दशा में उक्त संस्था के प्रबन्धाधिकरण को प्राप्त होते।

(5-ख) उपधारा (5) या उपधारा (5-क) के अधीन दिये गये किसी आदेश की अवधि प्रथमतः एक वर्ष से अधिक की न होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी संस्था के और ऐसी संस्था की या उसमें निहित सम्पति के उचित प्रबन्ध को अनवरत रूप से सुनिश्चित करने के लिये ऐसा करना इष्टकर है, तो वह समय-समय पर आदेश का प्रवर्तन ऐसी अवधि के लिये, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक न हो, जिसे वह निर्दिष्ट करे, बढ़ा सकती है किन्तु इस प्रकार कि उक्त आदेश के प्रवर्तन की कुल अवधि, जिसके अन्तर्गत उपधारा (5) या उपधारा (5-क) के अधीन प्रारम्भिक आदेश में निर्दिष्ट अवधि भी है, पांच वर्ष से अधिक न हो :

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि पांच वर्ष की उपरोक्त अवधि की समाप्ति के समय संस्था का कोई प्रबन्धाधिकरण वैध रूप से संगठित न हो तो प्राधिकृत नियन्त्रक तब तक संस्था का प्रबन्ध अपने हाथ में रखे रहेगा जब तक राज्य सरकार का समाधान न हो जाय कि वैध रूप से प्रबन्धाधिकरण का संघटन हो गया है :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार ऐसे आदेश को किसी भी समय विखण्डित कर सकती है।";

(घ) उपधारा (6) में शब्द "उपधारा (4) के खंड (1)" के बाद शब्द "या उपधारा (5) या उपधारा (5-क)" बढ़ा दिये जायं।

(ङ) उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(7) संस्था के प्रबन्ध तथा नियन्त्रण से सम्बन्धित (जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासन योजना भी है) अथवा संस्था की या उसमें निहित सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी अन्य अधिनियमिति या संलेख में दी गई किसी बात के असंगत होते हुये भी उपधारा (4) या उपधारा (5) या उपधारा (5-क) के अधीन दिया गया कोई आदेश या निदेश प्रभावी होगा।"

(च) उपधारा (8) में शब्द "उपधारा (4) या उपधारा (5)" के स्थान पर शब्द "उपधारा (4), उपधारा (5) या उपधारा (5-क)" रख दिये जायं ;

ण 3—किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम की धारा 16-घ के अधीन दिया गया या दिये जाने के लिए तात्पर्यित प्रत्येक आदेश इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त धारा के अधीन दिया गया समझा जायेगा और उसका इसी प्रकार निर्वहन किया जायेगा और वैध तथा प्रभावी समझा जायेगा और सदैव से ही वैध तथा प्रभावी समझा जायेगा मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान अवसरों पर प्रवृत्त थे, और तदनुसार, उक्त धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो प्राधिकृत नियंत्रक का कार्य करें या करने के लिये तात्पर्यित हो, किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही विधि के प्राधिकार से किया गया या की गई और सदैव से किया गया या की गई समझी जायेगी।

पी० एस० डू० पी०—ए० पी० 141 जनरल (लेग०)—1972—1,834+50 (मे०)।

THE INTERMEDIATE EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 1972

(U. P. ACT NO. 29 OF 1972)

[*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Intermediate Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 1972.]

AN

ACT

further to amend the Intermediate Education Act, 1921

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-second Year of the Republic of India as follows :— U. P. Act II of 1921.

1. This Act may be called the Intermediate Education (Amendment) Act, 1972. Short title.

2. In section 16-D of the Intermediate Education Act, 1921 (hereinafter referred to as the principal Act)— Amendment of section 16-D of U. P. Act II of 1921.

(*a*) in sub-section (4), *for* the first proviso thereto and the paragraph immediately preceding it the following paragraph and provisos shall be *substituted*, namely:—

"The period for which such order may be made shall not exceed one year in the first instance :

Provided that if the State Government is of opinion that it is expedient so to do in order to continue to secure the proper management of the institution, it may from time to time extend the operation of the order for such period, not exceeding one year at a time, as it may specify, so, however, that the total period of the operation of the order, including the period specified in the initial order under this sub-section, does not exceed five years :

Provided further that the State Government may at any time revoke the order ;"

(*b*) in sub-section (5), *for* the words "the institution were not taken over" the words "no order were made" shall be *substituted*, and the following proviso thereto shall be *inserted*, namely :—

"Provided that nothing in this sub-section shall be construed to confer on the Authorised Controller the power to transfer any such property (except by way of letting from month to month in the ordinary course of management) or to create any charge thereon (except as a condition of receipt of any grant-in-aid of the institution from the State Government)" ;

(*c*) *after* sub-section (5), the following sub-sections shall be *inserted*, namely :—

"(5-A) If on receipt of a recommendation referred to in sub-section (4) the State Government is satisfied that the circumstances mentioned in para (*a*) or para (*b*) of that sub-section exists and is further satisfied that for special and exceptional reasons, which shall be recorded, action under that sub-section will not be adequately effective and that in the interest of the institution it is necessary that the management of that institution be immediately handed over to an Authorised Controller, the State Government may by an order, for such period as may be specified in the order, appoint an Authorised Controller and that Authorised Controller may take over the management of the institution including management of the land, buildings, funds and other assets belonging to or vested in the institution to the exclusion of the management or any such person, and whenever the

---

(For Statement of Objects and Reasons, please *see Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated August 30, 1971.)

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on January 5, 1972, and by the Uttar Pradesh Legislative Council on January 11, 1972.)

(Received the Assent of the President on June 29, 1972 under Article 201 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated July 3, 1972.)

Authorised Controller so takes over the management he shall, subject only to such restrictions as the State Government may impose, have in relation to the management of the institution all such powers and authority as the management would have if no order were made under this sub-section or sub-section (4).

(5-B) The period for which an order may be made under sub-section (5) or sub-section (5-A) shall not exceed one year in the first instance :

Provided that if the State Government is of opinion that it is expedient so to do in order to continue to secure the proper management of the institution and the property belonging to or vested in the institution, it may from time to time extend the operation of the order for such period, not exceeding one year at a time, as it may specify, so however, that the total period of the operation of the order, including the period specified in the initial order under sub-section (5) or sub-section (5-A) does not exceed five years:

Provided further that if at the expiration of the said period of five years there is no lawfully constituted management of the institution, the Authorised Controller shall continue to keep the management in his hands until the State Government is satisfied that a management has been lawfully constituted:

Provided further that the State Government may at any time revoke the order;" ;

(*d*) in sub-section (6) *after* the words "clause (i) of sub-section (4)" the words "or sub-section (5) or sub-section (5-A)", shall be *inserted*;

(*e*) *for* sub-section (7) the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(7) Any order made or direction given under sub-section (4) or sub-section (5) or sub-section (5-A) shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other enactment or instrument relating to the management and control of the institution (including any scheme of administration) or relating to the property belonging to or vested in the institution."

(*f*) in sub-section (8), *for* the words "sub-section (4) or sub-section (5)" the words "sub-section (4), sub-section (5) or sub-section (5-A)" shall be *substituted*.

Validation

3. Notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court or other authority to the contrary, every order made or purporting to have been made under section 16-D of the principal Act before the commencement of this Act shall be deemed to have been made under that section as amended by this Act and shall be so interpreted and be deemed to be, and always to have been, as valid and effective as if the provisions of this Act were in force at all material times, and accordingly, anything done or any action taken by the State Government or by any person acting as or purporting to act as Authorised Controller under the said section shall be deemed to be, and always to have been, done or taken by authority of law.

PSUP—A. P. 142 Genl. (Leg.)—1972. 1,852+50. (M).

Authorised Controller so takes over the management he shall, subject only to such restrictions as the State Government may impose, have in relation to the management of the institution all such powers and authority as the management would have if no order were made under this sub-section or sub-section (4).

(5-B) The period for which an order may be made under sub-section (5) or sub-section (5-A) shall not exceed one year in the first instance :

Provided that if the State Government is of opinion that it is expedient so to do in order to continue to secure the proper management of the institution and the property belonging to or vested in the institution, it may from time to time extend the operation of the order for such period, not exceeding one year at a time, as it may specify, so however, that the total period of the operation of the order, including the period specified in the initial order under sub-section (5) or sub-section (5-A) does not exceed five years:

Provided further that if at the expiration of the said period of five years there is no lawfully constituted management of the institution, the Authorised Controller shall continue to keep the management in his hands until the State Government is satisfied that a management has been lawfully constituted:

Provided further that the State Government may at any time revoke the order;" ;

(*d*) in sub-section (6) *after* the words "clause (i) of sub-section (4)" the words "or sub-section (5) or sub-section (5-A)", shall be *inserted*;

(*e*) *for* sub-section (7) the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(7) Any order made or direction given under sub-section (4) or sub-section (5) or sub-section (5-A) shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other enactment or instrument relating to the management and control of the institution (including any scheme of administration) or relating to the property belonging to or vested in the institution."

(*f*) in sub-section (8), *for* the words "sub-section (4) or sub-section (5)" the words "sub-section (4), sub-section (5) or sub-section (5-A)" shall be *substituted*.

Validation

3. Notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court or other authority to the contrary, every order made or purporting to have been made under section 16-D of the principal Act before the commencement of this Act shall be deemed to have been made under that section as amended by this Act and shall be so interpreted and be deemed to be, and always to have been, as valid and effective as if the provisions of this Act were in force at all material times, and accordingly, anything done or any action taken by the State Government or by any person acting as or purporting to act as Authorised Controller under the said section shall be deemed to be, and always to have been, done or taken by authority of law.

PSUP—A. P. 142 Genl. (Leg.)—1972. 1,852+50. (M).